आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शुक्रवार 03.04.2026
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- राज्य में व्यवसायिक एलपीजी सिलेण्डरों के वितरण के लिए नई एस.ओ.पी लागू। विवाह समारोह के लिए विशेष प्रावधान।
- चारधाम यात्रा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दस अप्रैल को राज्य के सात ज़िलों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी।
- उत्तराखंड पुलिस "राष्ट्रपति पुलिस कलर" से सम्मानित।
- मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कुंभ मेले का दिव्य और भव्य आयोजन सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्य समय से पूरे करने के निर्देश दिए।

एलपीजी वितरण

उत्तराखंड में व्यवसायिक एलपीजी सिलेण्डरों के वितरण के लिए नई संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया–एसओपी लागू कर दी गई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव आनंद स्वरूप ने बताया कि राज्य में बढ़ती मांग और आपूर्ति संतुलन को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है। एक रिपोर्ट–

सचिव आनंद स्वरूप ने बताया कि राज्य को व्यवसायिक एलपीजी के लिए कुल 66 प्रतिशत कोटा मिल गया है। इसमें पहले से निर्धारित 40 प्रतिशत के अलावा 20 प्रतिशत केंद्र सरकार और 6 प्रतिशत अतिरिक्त कोटा शामिल है। नई व्यवस्था का उद्देश्य विभिन्न उपभोक्ता वर्गों के बीच संतुलित और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करना है, ताकि चारधाम यात्रा, पर्यटन और अन्य आवश्यक सेवाओं पर किसी तरह का असर न पड़े।

नई एसओपी के तहत अलग–अलग उपभोक्ता श्रेणियों के लिए सिलेण्डरों का दैनिक वितरण तय किया गया है। इसमें होटल और रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट और ढाबों के साथ–साथ औद्योगिक क्षेत्रों और अन्य आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी गई है। कुल मिलाकर प्रतिदिन 6 हजार 310 सिलेण्डरों के वितरण की व्यवस्था की गई है।

राज्य में गैस की आपूर्ति तेल एवं गैस कंपनियों द्वारा उनकी बाजार हिस्सेदारी के अनुसार की जाएगी और जिलाधिकारियों को इसकी जानकारी दी जाएगी, ताकि व्यवस्था पर निगरानी बनी रहे।

जनपदवार कोटा भी तय किया गया है, जिसमें देहरादून को सबसे अधिक 31 प्रतिशत आवंटन मिला है। इसके बाद हरिद्वार और नैनीताल को 13–13 प्रतिशत, उधमसिंह नगर को 9 प्रतिशत और अन्य जिलों को उनकी आवश्यकता के अनुसार कोटा दिया गया है।

विवाह समारोहों के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है, जिसमें अधिकतम दो व्यवसायिक सिलेण्डर की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए संबंधित जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी और निर्धारित अवधि के बाद यह कोटा सामान्य श्रेणियों में वापस समायोजित कर दिया जाएगा।

तैयारियां

चारधाम यात्रा के दौरान आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने तैयारियां तेज कर दी हैं। गृह मंत्रालय के निर्देश पर 10 अप्रैल को चारधाम यात्रा को लेकर राज्य के सात ज़िलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आपात स्थितियों से निपटने की क्षमता का परीक्षण किया जाएगा।

यूएसडीएमए देहरादून में आयोजित बैठक में चारधाम यात्रा से जुड़े जिलों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों को मॉक ड्रिल के संचालन के संबंध में दिशा–निर्देश दिए गए। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने कहा कि यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी विभाग पूरी तरह तैयार हैं और यह अभ्यास सभी संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय और तैयारी को परखने के लिए किया जा रहा है।

यह मॉक ड्रिल उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी और देहरादून सहित सात जिलों में आयोजित होगी। इसका संचालन राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से किया जाएगा।

मॉक ड्रिल के दौरान विभिन्न आपदा परिदृश्यों जैसे सड़क दुर्घटना, हेलीकॉप्टर दुर्घटना, भूकंप, आग, भगदड़, खराब मौसम, बाढ़, आकाशीय बिजली, भूस्खलन और हिमस्खलन जैसी स्थितियों में विभागों की तैयारियों का परीक्षण किया जाएगा। साथ ही विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों, सेना, एयर फोर्स, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय की भी जांच की जाएगी।

तैयारियां

बदरीनाथ धाम की यात्रा शुरू होने से पहले तैयारियों को तेज कर दिया गया है। नगर पंचायत बदरीनाथ ने धाम में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है और इसके लिए 50 सदस्यीय दल को बदरीनाथ भेजा गया है।

यह दल धाम में पैदल मार्गों की मरम्मत, पथ प्रकाश, शौचालय और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ अन्य यात्री सुविधाओं को व्यवस्थित करने का कार्य कर रहा है।

जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि यात्रा के सुचारु संचालन के लिए सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं। सड़क मार्गों के सुधार के लिए संबंधित एजेंसियों को काम करने को कहा गया है, जबकि स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों को भी यात्रा से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी जरूरी व्यवस्थाओं को चाक–चौबंद किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

राष्ट्रपति पुलिस कलर

उत्तराखंड पुलिस को "राष्ट्रपति पुलिस कलर" से सम्मानित किया गया है। यह भारत में पुलिस बलों को दिया जाने वाले सर्वोच्च सामूहिक सम्मान है। यह भारत सरकार द्वारा उन पुलिस बलों इकाइयों को दिया जाता है, जिन्होंने लंबे समय तक उत्कृष्ट सेवा, बहादुरी, अनुशासन और उच्च पेशेवर क्षमता का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे राज्य के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ सहित सभी अधिकारियों और जवानों को इस उपलब्धि पर बधाई दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मान उत्तराखंड पुलिस की कर्तव्यनिष्ठा, समर्पण और उत्कृष्ट सेवा की राष्ट्रीय पहचान है। इसके साथ ही उत्तराखंड पुलिस देश के उन चुनिंदा पुलिस बलों में शामिल हो गई है, जिन्हें यह सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून–व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण, आपदा प्रबंधन और आधुनिक तकनीक के उपयोग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर यह सम्मान मिला है। दुर्गम परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद पुलिस ने अपने दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन किया है।

पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने इसे उत्तराखंड पुलिस के इतिहास का महत्वपूर्ण क्षण बताते हुए कहा कि यह उपलब्धि सभी पुलिसकर्मियों के समर्पण और सेवा भावना का परिणाम है।

समीक्षा

हरिद्वार में कुंभ मेला–2027 की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मेला नियंत्रण भवन में अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भी विचार–विमर्श कर सुझाव लिए गए।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि कुंभ मेले का दिव्य और भव्य आयोजन सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्य समय से पूरे किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी को गंभीरता से लिया जाएगा। हरिद्वार में सीवर लाइन निर्माण को प्राथमिकता देते हुए खोदी गई सड़कों को तुरंत ठीक करने और अपर रोड का कार्य एक सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए गए, जबकि शेष कार्य 30 जून तक समाप्त करने को कहा गया।

मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में गंदा पानी गंगा में न जाए और सभी नालों को सीवर लाइन से जोड़ा जाए। उन्होंने निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है।

स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का निर्माण जल्द पूरा करने और आवश्यक सुविधाएं शुरू करने को कहा गया। मेले के दौरान बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए एंबुलेंस और बोट एंबुलेंस की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई।

महायोजना 2031

ऋषिकेश के सुनियोजित विकास के लिए महायोजना–2031 को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सचिवालय में आयोजित बैठक में इस योजना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर मंथन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सचिव आवास डॉ. आर राजेश कुमार ने की, जिसमें टिहरी, पौड़ी और देहरादून के अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में तपोवन क्षेत्र की चुनौतियों पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि पिछले वर्षों में यहां अनियोजित और अवैध निर्माण तेजी से बढ़े हैं, जिससे यातायात, पार्किंग और सीवरेज जैसी सुविधाओं पर दबाव बढ़ा है और स्थानीय लोगों के साथ–साथ पर्यटकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

महायोजना–2031 में इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रावधान किए गए हैं। जिन क्षेत्रों में पहले से होटल और व्यावसायिक गतिविधियां विकसित हो चुकी हैं, उन्हें पर्यटन उपयोग क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। साथ ही भविष्य में अनियोजित निर्माण पर रोक लगाने के लिए सख्त नियम भी शामिल किए गए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि महायोजना को संबंधित प्राधिकरणों से स्वीकृति मिलने के बाद जनसुनवाई और सुझावों के आधार पर संशोधित किया गया है और अब यह अंतिम चरण में है। तीनों जिलों से प्राप्त सुझावों को 15 दिनों के भीतर समेकित कर शासन को भेजा जाएगा, ताकि योजना को जल्द लागू किया जा सके।

सरकार का मानना है कि इस योजना के लागू होने से ऋषिकेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

दून पुस्तक महोत्सव

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, शिक्षा मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार के संयुक्त प्रयासों से कल से 12 अप्रैल तक देहरादून के परेड ग्राउंड में दून पुस्तक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, के निदेशक युवराज मलिक ने बताया कि ये आयोजन पुस्तकों, विचारों और संस्कृति के संगम के रूप में पाठकों, लेखकों और कलाकारों को एक मंच पर लाएगा।